



33

समय: न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल न्यायिकर कैम्प जबलपुर म० प्र०

रिवीज प्र० प्र०
 निगरानी = 5960/2018/जबलपुर/श्र.रु
 सन

प्रमाण सिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह ठाडुर निवासी
 वाई नं. 7 गढिया मोहल्ला, सिहौरा जिला जबलपुर

--रिवीज नर्ता/आर०

693

श्री. राजस्व मण्डल...
 अधीक्षक
 न्यायिकर कमिश्नर जबलपुर संभाग
 12 0 SEP 2018

1. पी. आर. पाण्डे,
2. सुरेंद्र कुमार दुबे
3. एस. * लुधवाहा
4. विजयेश्वर पटेल

सभी निवासी वाई नं. 7 गढिया मोहल्ला तहसील सिहौरा
 जिला जबलपुर

--उत्तरवादी ग/अप०

रिवीज अन्तर्गत धारा 51 म० प्र० श्र. राजस्व संहिता 1959

रिवीज नर्ता को और से निम्न विनय है:-

न्यायालय श्रीमान अति. कमिश्नर महोदय संभाग जबलपुर द्वारा रा. प्र. क्र. 0807/
 अपील/2018-18 प्रमाण सिंह वि. पी. आर. पाण्डेय वगै. आदेश दिनांक 29.6.18 से
 व्यथित होकर निम्न तथ्यों आधारों पर यह रिवीज समयावधि के अंदर पेश की



जिसकी है:-

रिवीज के तथ्य
 =====

- 1- प्रकरण संक्षिप्त इस प्रकार है कि रिवीज नर्ता के द्वारा अपील में लैब किया गया कि
 गढ़वालिक सिहौरा वाई नं. 7 गढिया मोहल्ला में लगभग 150 वर्ष पूर्व से हनुमानजी मंदिर
 एवं कुंआ बना है। उक्त मंदिर एवं कुंआ में जाने का रास्ता पहले खेत की मेड़ से गुजरता
 था लेकिन 1917 में मोहल्ला के जास्तकार मूढा देवा बिहारों एवं बुधिया देवा फतह सिंह



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-जबलपुर/भू.रा./2018/ 5960

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6/12/18	<p>निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 807/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-18 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 29-6-18 पारित करके आवेदक की अपील इस आधार पर निरस्त की है :-</p> <p>खसरा नं. 136 की सरकारी भूमि से आने जाने का रास्ता है जो मौके पर कंक्रीट का रास्ता है जिसका उपयोग उत्तरवादीगण करते हैं। उक्त रास्तो पर अपीलार्थी द्वारा दीवाल खड़ी कर दी गई है जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। जिसे हटाये जाने के आदेश तहसीलदार सिहोरा द्वारा दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को स्थिर रखते हुये शासकीय भूमि मद रास्ता में किये गये निर्माण को हटाये जाने का आदेश पारित किये जाने में विधि संबंधी कोई त्रुटि नहीं की गई है।</p> <p>उपरोक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 29-6-18 से अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के आदेश दिनांक 31-3-17 को तथा तहसीलदार सिहोरा के आदेश दिनांक 31-12-15 को यथावत् रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में विचार का औचित्य नहीं है।</p> <p>3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी में सुनवाई के पर्याप्त आधार नहीं होने से निरस्त की जाती है।</p>	<p>सदस्य</p>